an>

Title: Alleged disadvantage to the candidates appearing for Civil Services Examinations in Hindi and other Indian languages.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन का और इस देश का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि एक ओर हमारे देश के संविधान, कानून और नियम इस सदन ने पास किए हैं, वहीं दूसरी ओर उस कानून को पास करने वाले लोग जिनके माध्यम से कानून पास होना है और उनकी परीक्षा के लिए जो योग्यता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तय की गयी हैं, उसमें बड़ा अजीब विरोधाभास है। एक ओर हमारे संविधान में पारित किया गया कि हमारे देश की राजभाषा हिन्दी हो, हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो, वहीं तमाम शासकीय काम जिन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से होने हैं, उनकी परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से होती है, उस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो तरीका अपनाया गया है, मैं समझता हूं सभापति महोदय इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके पीछे कितना षडयंत्र होगा, यह तो आपको इसकी सच्चाई को सुनने के बाद स्वयं महसूस होगा।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यूपीएससी के ऊपर प्रशासनिक और तमाम पदों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी है और उस आयोग ने वर्ष 2010 का जो पाठ्यक्रम रखा था, उस पाठ्यक्रम में गांव के गरीब, किसान, आप स्वयं रूरल बैकग्राउंड से हैं और इस बात को जानते हैं कि ग्रामीण अंचल के नौजवान जो परीक्षाओं में पास होते थे, वर्ष 2011 से, यह अलग बात है कि विगत सरकार के कार्यकाल लेकिन हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार होगा। वर्ष 2011 से जब से सी-सैट लागू हुआ है, तब से इतनी विडम्बना है कि यदि हम आपके सामने आंकड़े पेश करेंगे तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे।

सभापति महोदय, अगर हम यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षाओं की बात करें, तो जहां 2008 में प्री एग्जाम में 45 फीसदी, 2009 में 42 फीसदी, 2010 में 35 फीसदी छात्र ग्रामीण अंचलों, हिन्दी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के लोग उत्तीर्ण हुए थे। वहीं सी-सैट की परीक्षा में जब से यह माध्यम लागू हुआ है, 2011 में यह संख्या घटकर 11 फीसदी हो गई है और 2012 में यह संख्या 16 फीसदी हो गई। यह प्री परीक्षा का हाल है। मेन्स परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल परिणाम आए, उन परिणामों की जब हम आपसे चर्चा करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। आप एक लाइन में कह दीजिए कि आपकी क्या मांग है?

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय सभापति जी, इस सत्र में आपके पीठासीन होते हुए मैं पहली बार बोल रहा हूं। यह विषय इतना गंभीर है और मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं।

माननीय सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे मालूम है। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। तीन मिनट हो गए।

â€¦(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है। 2009 में हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 24 फीसदी थी और 2013 का जो परिणाम आया, वह प्रतिशत केवल 2.3 फीसदी रह गया है।

माननीय सभापति : कितना प्रतिशत होना चाहिए?

â€¦(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : जो पुराना पाठ्यक्रम था, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं होनी चाहिए। यह बात हम तो कह ही रहे हैं। संघ आयोग ने एक समिति गठित की थी।...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हम कभी आपके सामने जिद नहीं करेंगे। हमेशा अनुशासित रहेंगे। संघ आयोग ने श्री अरुण निगवेकर समिति गठित की थी। उस आयोग की समिति की सिफारिशों में भी इस बात को कहा गया कि यह जो सी-सैट परीक्षा की प्रणाली है, यह प्रणाली शुद्ध रूप से ग्रामीण छात्रों की विरोधी है। हिन्दी भाषा और भारतीय भाषाओं की विरोधी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सी-सैट की प्रणाली को खत्म करें जिससे कि ग्रामीण अंचलों के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में आ सकें।

माननीय सभापति : श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उठाये गये विषय के साथ

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एसोशिएट किया जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय सभापति जी, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा हुई है, इसके खिलाफ यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों लोग जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से तैयारी करते हैं, वे लोग धरने पर बैठे हैं और पिछले दो-तीन दिनों से वे भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसी सदन में तीसरी चौथी बार यह मामला उठ रहा है। पन्द्रहवीं लोक सभा में भी यह मामला कई बार उठा था। यह भारतीयता और भारतीय भाषाओं के खिलाफ एक साजिश है। इस साजिश को रचने वाले जो लोग हैं, वे आज भी भारतीय वेशभूषा में अंग्रेजों की परम्परा को जबरन भारत के अंदर लादना चाहते हैं और इसलिए आपके माध्यम से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि एक तो जो प्रारम्भिक परीक्षा में सी-सैट प्रणाली का जो दूसरा प्रश्नपत्र है, उसको हटाया जाए क्योंकि यह प्रणाली मानविकी, गैर-तकनीकी, गैर-प्रबंधन, स्नातक छात्रों के प्रतिकूल तथा तकनीकी एवं प्रबंधन विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अनुकूल है। इसलिए इस असमान प्रतिस्पर्धा यानी सी-सैट को समाप्त किया जाए। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में गलत और जटिल अनुवाद न किये जाएं क्योंकि जो अंग्रेजी के अनुवाद होते हैं, आप संसद में भी देखते होंगे कि कितने कठिन और जटिल होते हैं। सामान्य व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाएगा। उसको उस प्रकार का न किया जाए। मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्नपत्र, स्तर हिन्दी या भारतीय भाषा के प्रश्नपत्र के समान ही रखा जाए। उसे जानबूझकर ज्यादा कठिन न किया जाए। सामान्य अध्ययन की जो मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। उसमें भी भेदभाव हो रहा है। उसको भी समाप्त किया जाए। इसके अलावा जो साक्षात्कार में अन्याय होता है, जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनको अधिक नम्बर दिये जाते हैं और जो भारतीय भाषाओं में या किसी भी भारतीय भाषा में जो परीक्षार्थी शामिल होता है, उसको वहां पर हतोत्साहित किया जाता है। यह ठीक नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहते हैं और साथ ही कहना भी चाहते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है, यहां पर माननीय मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे इस बात का आग्रह करूंगा कि इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए कि भारतीयता के खिलाफ, भारतीय भाषाओं के खिलाफ देश की सर्वोच्च परीक्षाओं के माध्यम से जो एक षडयंत्र रचा जा रहा है, उसका पटाक्षेप होना चाहिए और इस देश की जो होनहार प्रतिभा आज अनशन और भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर है, कम से कम उनकी बातों को सुना जाना चाहिए।

माननीय सभापति: श्री जगदम्बिका पाल जी, यह आपका विषय वैसे तारांकित विषय में डिसकस हो गया है, फिर भी आप बोल रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): ठीक है। इनके बाद हम बोल लेंगे।

माननीय सभापति : श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री पी.पी.चौधरी और

श्री ओम बिरला को एसोशिएट किया जाए।